

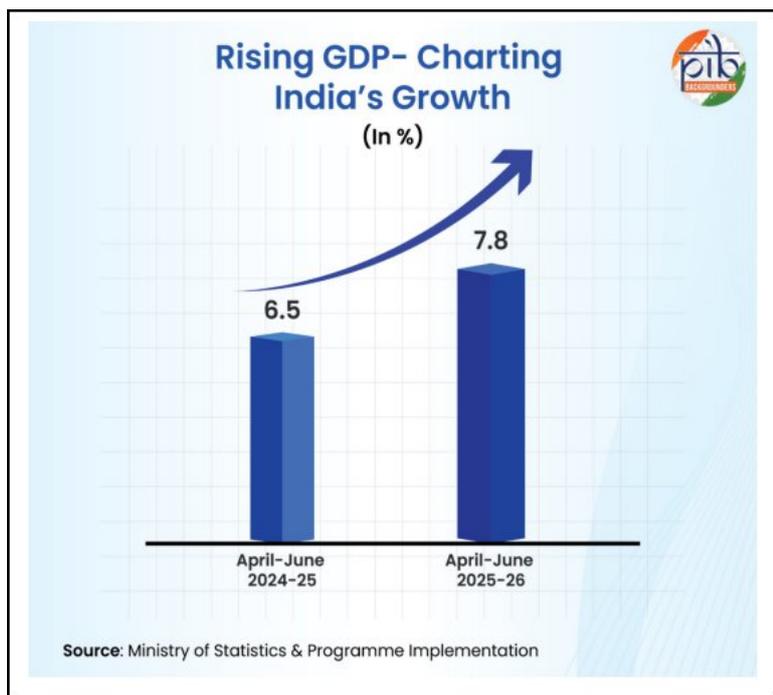
भारत की जीडीपी वृद्धि: विकास की कहानी

मुख्य आकर्षण:

- वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 7.8% बढ़ने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह 6.5% रहेगी।
- वर्ष 2030 तक भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
- भारत में रोज़गार में वृद्धि हुई है और पिछले एक दशक में 17 करोड़ नौकरियाँ सृजित हुई हैं।
- अगली पीढ़ी के जीएसटी जैसे नए सुधार हो रहे हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना शुरू की गई है।

प्रस्तावना

भारत की मजबूत सेवा क्षेत्र ने लगातार दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि को आशा से बेहतर बनाने में मदद की है जो अप्रैल-जून 2025 के लिए 7.8% के प्रभावशाली उच्च स्तर पर पहुंच गई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में तेज वृद्धि ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत किया है।

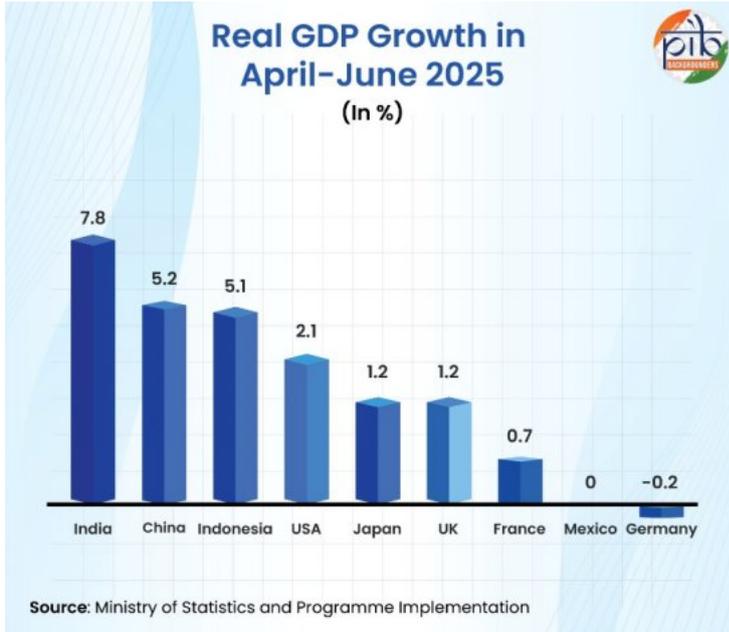


वर्तमान में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत 2030 तक अनुमानित 7.3 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। यह गति निर्णायक शासन, दूरदर्शी सुधारों और सक्रिय वैश्विक भागीदारी से प्रेरित है। उल्लेखनीय रूप से, विकास में तेज़ी आ रही है, और वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष पहले 6.5% थी।

यह वृद्धि मजबूत घरेलू माँग और परिवर्तनकारी नीतिगत सुधारों से प्रेरित है, जो भारत को वैश्विक पूंजी के लिए आकर्षित करते हैं। घटती मुद्रास्फीति,

बढ़ते रोज़गार और उत्साहजनक उपभोक्ता भावना के साथ, आने वाले महीनों में निजी खपत से जीडीपी वृद्धि को और गति मिलने की उम्मीद है।

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (जीडीपी)



सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाकर अर्थव्यवस्था के आकार को दर्शाता है। वास्तविक जीडीपी, जो मुद्रास्फीति के प्रभावों को हटाकर अर्थव्यवस्था के उत्पादन को मापती है, 2024-25 की पहली तिमाही में 6.5% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी ₹47.89 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह ₹44.42 लाख करोड़ थी, जो 7.8% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है।

- वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में, कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन तथा खनन और उत्खनन

सहित संबद्ध क्षेत्र में 3.7% की वृद्धि हुई, जो पिछले वित्त वर्ष इसी अवधि में 1.5% थी।

- दूसरे क्षेत्र विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवाएं तथा निर्माण जैसी सेवाओं ने मजबूत वृद्धि दर्ज की, जिसमें विनिर्माण (7.7%) और निर्माण (7.6%) दोनों ने 7.5% की वृद्धि दर को पार कर लिया।
- तीसरे क्षेत्र ने स्थिर मूल्यों पर 9.3% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के 6.8% से अधिक है।

हमारे अनुसार, पहली तिमाही के आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था के बुनियादी लचीलेपन को दर्शाते हैं। यह अर्थव्यवस्था में मजबूत होती गति को दर्शाता है और यह मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद पर टिका है। आपूर्ति पक्ष में, हमने चौतरफा वृद्धि देखी है। विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में भी मजबूत वृद्धि देखी गई है। रबी की फसल और खरीफ की बुआई पिछली तिमाहियों से कहीं ज्यादा रही है। हमारे पास अच्छा बफर स्टॉक है। अच्छी बारिश हुई है... माँग पक्ष में प्राथमिक कारक घरेलू रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में, शुद्ध निर्यात माँग पक्ष में उतना योगदान नहीं देता। - अनुराधा ठाकुर, आर्थिक मामलों की सचिव, वित्त मंत्रालय

अप्रैल-जून 2025 में विकास में आई तेज़ी सेवा क्षेत्र की 9.3% की उच्च दर से प्रेरित है। सेवा क्षेत्र के सभी घटक, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ, वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ तथा लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ, तेज़ी से बढ़ रही हैं। जीवीए वृद्धि, जिसे गतिविधि स्तरों का एक सार्थक मादंड माना जाता है जो अप्रैल-जून 2025 में 7.6% के उच्च स्तर पर पहुँच गई। जीवीए की गणना सकल घरेलू उत्पाद से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों (सब्सिडी समायोजन के बाद अप्रत्यक्ष करों) को घटाकर की जाती है।

उल्लेखनीय है कि भारत का 2027 तक सकल घरेलू उत्पाद 4,26,45,000 करोड़ रुपये (5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंचने का अनुमान है और 2028 तक यह जर्मनी से आगे निकल जाएगा। 2030 तक भारत 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) किसी चुने हुए आधार वर्ष की तुलना में, एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर मासिक, में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की भौतिक मात्रा में परिवर्तन को मापता है। यह खनन, विनिर्माण और बिजली जैसे क्षेत्रों से औद्योगिक उत्पादों की एक "बास्केट" के उत्पादन को ट्रैक करता है, जिससे अर्थव्यवस्था के औद्योगिक प्रदर्शन की स्थिति और रुझानों के बारे में जानकारी मिलती है। यह आर्थिक नियोजन और सकल घरेलू उत्पाद में किसी क्षेत्र के योगदान का आकलन करने के लिए आवश्यक है।

- उल्लेखनीय रूप से, जुलाई 2025 के महीने के लिए आईआईपी वृद्धि दर 3.5% थी, जो जून 2025 के महीने में 1.5% की तुलना में प्रभावशाली वृद्धि थी, जो विनिर्माण क्षेत्र में 5.4% की वृद्धि से प्रेरित थी।
- विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, 23 उद्योग समूहों में से 14 ने जुलाई 2024 की तुलना में जुलाई 2025 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। जुलाई 2025 के महीने के लिए शीर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ता मूल धातुओं का निर्माण (12.7%), विद्युत उपकरणों का निर्माण (15.9%) और अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण (9.5%) थे।

ग्राहक आधारित जीएसटी वृद्धि

1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के आठ वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2017 में लागू किए गए जीएसटी ने अप्रत्याक्ष करों के जाल को एक एकीकृत प्रणाली से बदल दिया, जिससे अनुपालन सरल हुआ, कीमतों में कमी हुई और राज्यों के बीच वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही संभव हुई।

भारत जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित 5%, 12%, 18% और 28% की चार-स्तरीय संरचना का पालन करता है। आज, 1.52 करोड़ से अधिक सक्रिय जीएसटी पंजीकरण हैं, जिनमें से लगभग आधे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक से हैं। उत्साहजनक बात यह है कि 20% करदाताओं में कम से कम एक महिला सदस्य शामिल है, और 14% पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं, जो बढ़ती औपचारिकता और समावेशिता को दर्शाता है।

जीएसटी ने राज्यों के बीच मूल्य अभिसरण को भी बढ़ावा दिया है, जिससे राष्ट्रीय समकारी के रूप में इसकी भूमिका मज़बूत हुई है। भविष्य में, अगली पीढ़ी के सुधार अक्टूबर 2025 में शुरू किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं पर कर कम करना, एमएसएमई अनुपालन को आसान बनाना और एक अधिक पारदर्शी, नागरिक-अनुकूल कर प्रणाली बनाना है।

पूंजीगत व्यय (CAPEX)

पूंजीगत व्यय (CAPEX) राष्ट्रीय निवेश में योगदान देने और अर्थव्यवस्था में भौतिक परिसंपत्तियों के भंडार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जो न केवल कई वर्षों तक राजस्व उत्पन्न करती हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों की समग्र परिचालन में भी सुधार करती हैं। CAPEX उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए आवश्यक है जिससे त्वरित आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। यह वृद्धि, बदले में, रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है और श्रम उत्पादकता को बढ़ाती है। **2024-25 में, CAPEX ₹10.52 ट्रिलियन था, जो संशोधित अनुमानों से अधिक था।**

उल्लेखनीय रूप से, व्यय की गुणवत्ता, जिसे पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में मापा जाता है, पिछले तीन वर्षों से 0.27 से अधिक बनी हुई है, जो कोविड-पूर्व औसत से लगभग दोगुना है। जुलाई-नवंबर 2024 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 8.2% बढ़ा और इसके और बढ़ने की उम्मीद है।

अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के दृष्टिकोण से, **वास्तविक निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) के आँकड़े प्रभावशाली रहे हैं।** PFCE, परिवारों और उनको सेवा देने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसे मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता है ताकि केवल मूल्य परिवर्तनों के बजाय उपभोग की वास्तविक मात्रा दर्शाई जा सके। इसी प्रकार, **सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (GFCE)**, जो अपनी आबादी की सामूहिक आवश्यकताओं को सीधे पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार के खर्च को दर्शाता है, में भी सुधार हुआ है।

- पीएफसीई ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान 7.0% की वृद्धि दर दर्ज की है, जबकि पिछली इसी अवधि में 8.3% की वृद्धि दर दर्ज की गई थी, जो ग्रामीण मांग में तेजी के कारण संभव हुई है।
- वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान जीएफसीई नाममात्र की दृष्टि से 9.7% की वृद्धि दर दर्ज करेगा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 4.0% की वृद्धि दर दर्ज की जाएगी।

ग्रामीण मांग में तेजी से वृद्धि उपभोग के लिए शुभ संकेत है। उच्च सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और बेहतर होती व्यावसायिक उम्मीदों के बल पर निवेश गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में कमी

मुद्रास्फीति, मुद्रा के संदर्भ में वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत में वृद्धि है और भारत में इसे दो संकेतकों, **थोक मूल्य सूचकांक (WPI)** और **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** के आधार पर मापा जाता है। WPI उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है और इसकी गणना प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन एवं बिजली तथा विनिर्मित उत्पादों के थोक मूल्य के आधार पर की जाती है। दूसरी ओर, CPI उन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है जिन्हें लोग दैनिक उपयोग के लिए खरीदते हैं, जैसे कि खाद्य एवं पेय पदार्थ, कपड़े और जूते, आवास, ईंधन एवं प्रकाश आदि।

भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। जुलाई 2025 में भारत की मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई, जो क्रय शक्ति में वृद्धि का संकेत देती है, जिससे परिवारों को राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था में स्थिरता का संकेत मिलेगा।

मुद्रा स्फीति	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)			
	वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही	वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही	वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही	जुलाई-2025
सीपीआई मुद्रास्फीति	4.9	3.7	2.7	1.55

खाद्य मुद्रास्फीति	8.9	4.1	0.6	-1.76
मूल स्फीति	3.1	3.9	4.3	3.9

• जुलाई, 2025 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित मुद्रास्फीति दर जुलाई, 2024 की तुलना में 1.55% रहेगी। जून, 2025 की तुलना में जुलाई, 2025 की मुख्य मुद्रास्फीति में 55 आधार अंकों की गिरावट आएगी। **यह जून, 2017 के बाद सबसे कम मुद्रास्फीति दर है।**

○ जुलाई 2025 में, खाद्य पदार्थों की कीमतें जुलाई 2024 की तुलना में 1.76% कम थीं, जिसे नकारात्मक मुद्रास्फीति या खाद्य पदार्थों में अपस्फीति कहा जाता है। **ग्रामीण क्षेत्रों में 1.74% और शहरी क्षेत्रों में 1.90% की गिरावट देखी गई।** जून 2025 की तुलना में, खाद्य मुद्रास्फीति में 75 आधार अंकों की गिरावट आई, जिसका अर्थ है कि

जुलाई में कीमतों में तेज़ी से गिरावट आई।

- यह **-1.76% जनवरी 2019 के बाद से सबसे कम खाद्य मुद्रास्फीति दर है**, जो दर्शाता है कि छह वर्षों में खाद्य कीमतें इतनी कम नहीं रही हैं।

उल्लेखनीय है कि **आरबीआई अपनी प्राथमिक मौद्रिक नीति रूपरेखा के रूप में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की नीति का पालन करता है**, जिसके तहत आरबीआई सीपीआई मुद्रास्फीति को ± 2 प्रतिशत अंकों की सहनशीलता सीमा के साथ 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य रखता है (अर्थात्, लक्ष्य सीमा 2% से 6% है) पिछली तीन तिमाहियों में, सीपीआई मुद्रास्फीति दर आरबीआई की $4\% \pm 2\%$ की सहनशीलता सीमा के भीतर रही है।

रोज़गार

भारत के रोज़गार बाज़ार में बड़ा बदलाव आया है, जो आज़ादी से पहले के दौर की एक बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से आज एक वैश्विक रूप से एकीकृत, तकनीक-संचालित अर्थव्यवस्था में देश के आर्थिक विकास को दर्शाता है। दशकों से, रोज़गार के पैटर्न अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों के साथ-साथ बदलते रहे हैं, और कार्यबल धीरे-धीरे कृषि से उद्योग की ओर और हाल ही में, सेवाओं और ज्ञान-आधारित क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हुआ है।



DID YOU KNOW?



INDIA'S DEMOGRAPHIC DIVIDEND IS BOOMING!

- The working-age population is set to grow from 735 million (2011) to 988.5 million (2036).
- Today, 64.2% of Indians are of working age – and for the next decade, this share will stay close to 65%, giving India one of the world's most favorable demographic profiles.

Source-Ministry of Statistics & Programme Implementation

भारत में रोजगार में वृद्धि हुई है, पिछले दशक में 17 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं, जो सरकार की युवा-केंद्रित नीतियों और उसके विकसित भारत विजन पर फोकस को दर्शाता है।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 49.8% से बढ़कर 2023-24 में 60.1% हो गई है। उल्लेखनीय रूप से, महिला एलएफपीआर 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है। यह ग्रामीण और शहरी सहित विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी को दर्शाता है। ग्रामीण भारत में महिला रोजगार में 96% की वृद्धि देखी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 43% की वृद्धि

देखी गई है।

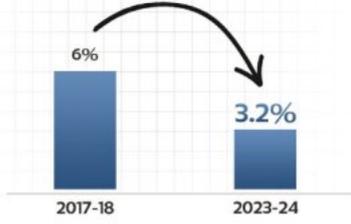
हाल ही में, अप्रैल-जून 2025 की तिमाही में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एलएफपीआर 55.0% थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 57.1% और शहरी क्षेत्रों में 50.6% थी। जुलाई 2025 में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एलएफपीआर 54.9% थी, जबकि जून 2025 के दौरान यह 54.2% थी।

इस तिमाही में, कृषि क्षेत्र में अधिकांश ग्रामीण श्रमिक कार्यरत थे (44.6% पुरुष और 70.9% महिलाएँ), जबकि शहरी क्षेत्रों में तृतीयक क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत था (60.6% पुरुष और 64.9% महिलाएँ) इस तिमाही के दौरान देश में औसतन 56.4 करोड़ व्यक्ति (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) कार्यरत थे, जिनमें से 39.7 करोड़ पुरुष और 16.7 करोड़ महिलाएँ थीं।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार का बोलबाला था (पुरुषों में 55.3% और महिलाओं में 71.6%), जबकि शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतन/वेतनभोगी रोजगार प्रमुख था (पुरुषों में 47.5% और महिलाओं में 55.1%)।

इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी दर (यूआर) में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो 2017-18 के 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। यह उत्पादक रोजगार में कार्यबल के बेहतर समावेश का संकेत देता है। इसी अवधि में, युवा बेरोजगारी दर 17.8% से घटकर 10.2% हो गई, जो इसे वैश्विक औसत 13.3% से नीचे रखती है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य 2024 में बताया गया है।

DECLINE IN UNEMPLOYMENT RATE



Source: Ministry of Labour & Employment

हाल ही में, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर जून 2025 में 5.6% से घटकर जुलाई 2025 में 5.2% हो गई। अप्रैल-जून 2025 तिमाही में, शहरी क्षेत्रों के लिए देखी गई 6.8% की तुलना में समग्र ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.8% पर आ गई।

पिछले दशक में **कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र** में रोजगार सृजन क्रमशः 19% और 36% तक बढ़ गया है। **विनिर्माण क्षेत्र में**, 2004 से 2014 के बीच रोजगार सृजन 6% था, जबकि पिछले दशक में यह बढ़कर 15% हो गया।

निवेश और पूंजी प्रवाह

एक दशक के संरचनात्मक सुधारों, निवेशक-अनुकूल नीतियों और बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता के बल पर, भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए तेज़ी से एक शीर्ष वैश्विक गंतव्य के रूप में उभरा है। वैश्विक रैंकिंग में सुधार और रणनीतिक पहलों के कारण, निवेशकों का विश्वास मज़बूत हुआ है। अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 81 अरब डॉलर का ऐतिहासिक विदेशी निवेश हुआ।

सरकार ने अब वार्षिक एफडीआई प्रवाह को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले पांच वर्षों के औसत 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, क्योंकि भारत बदलती आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच खुद को एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।

अप्रैल 2000 और दिसंबर 2024 के बीच संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) ₹89.85 लाख करोड़ (1.05 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया - जो वित्त वर्ष 2001 की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक है। उल्लेखनीय रूप से, अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इविवटी प्रवाह सालाना आधार पर 27% बढ़कर ₹3.40 लाख करोड़ (40.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया, जो निवेशकों के मज़बूत विश्वास को दर्शाता है। प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) उदारीकरण, GST और मेक इन इंडिया जैसे सुधार इस वृद्धि के प्रमुख चालक रहे हैं।

इसके अलावा, भारत के वित्तीय बाजारों ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है, जो मुख्य रूप से मज़बूत घरेलू निवेशक भागीदारी से प्रेरित है।

घरेलू संस्थागत निवेशक (DII)	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआईएस)
डीआईआई बड़े शुद्ध खरीदार बने रहे, जिन्होंने 16 जून, 2025 से 15 जुलाई, 2025 के बीच ₹44,269 करोड़ मूल्य की इविवटी खरीदी।	एफआईआई ने 16 जून, 2025 से 15 जुलाई, 2025 के बीच ₹33,336.8 मूल्य के इविवटी की तुलनीय शुद्ध खरीदारी की।

इसके अतिरिक्त, 18 जुलाई, 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 695.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 27 जून, 2025 को समाप्त सप्ताह में 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था।

वैश्विक स्तर पर भारत की विकास गाथा

भारत की विकास यात्रा मज़बूत व्यापक आर्थिक बुनियाद के सहारे वैश्विक सुखियों में बनी हुई है। आरबीआई को उम्मीद है कि विकास की गति 2025-26 तक जारी रहेगी, जबकि अन्य अनुमान भी इसी आशावाद को दोहराते हैं।

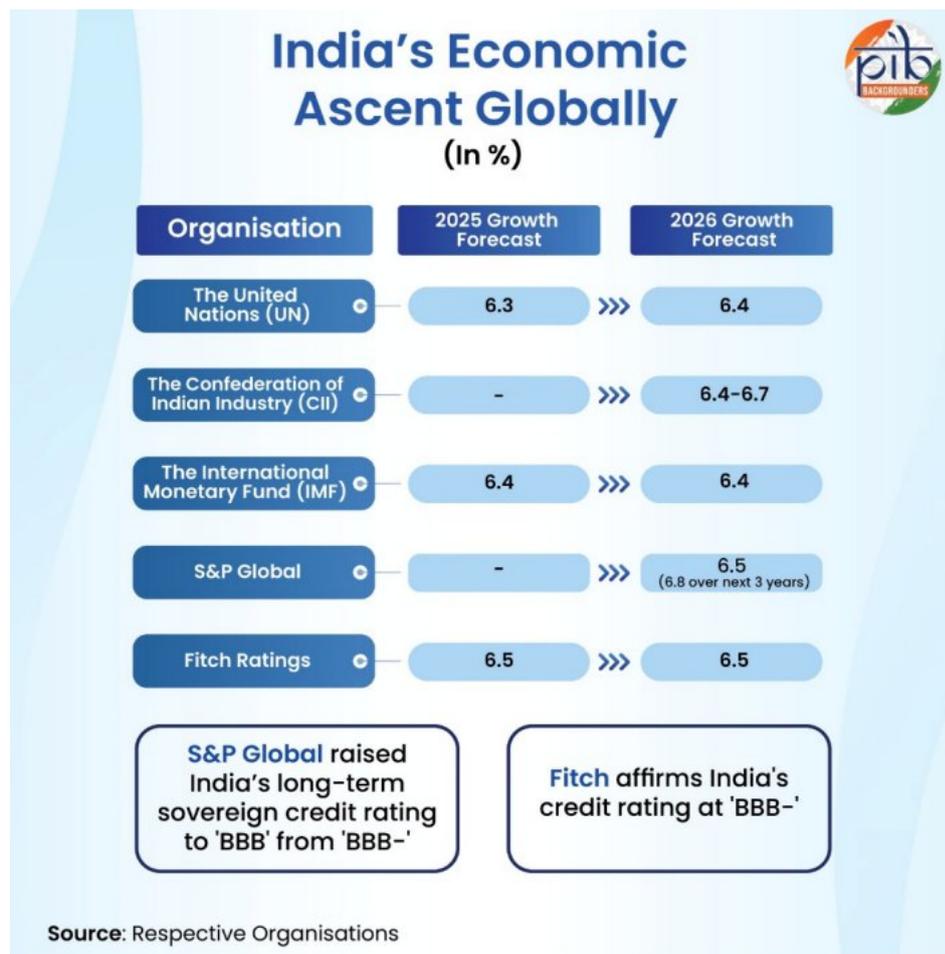
उदाहरण के लिए, **संयुक्त राष्ट्र (यूएन)** ने 2025 में 6.3% और 2026 में 6.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि **भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)** ने अपना अनुमान थोड़ा ज़्यादा 6.40 से 6.70% तक रखा है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी इसका अनुसरण किया और 2025 और 2026 दोनों के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.4% कर दिया। इससे पहले अप्रैल 2025 के अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य में, आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% और 2026 के लिए 6.3% रहने का अनुमान लगाया था।

एसएंडपी ग्लोबल ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'बीबीबी-' से बढ़ाकर 'बीबीबी' कर दिया है, जबकि अल्पकालिक रेटिंग को 'ए-3' से बढ़ाकर 'ए-2' कर दिया है। भारत की बढ़ती वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए, हस्तांतरण और परिवर्तनीयता मूल्यांकन को भी 'BBB+' से सुधारकर 'A-' कर दिया गया है। S&P ने पिछली बार जनवरी 2007 में भारत की रेटिंग को 'BBB-' किया था, इसलिए यह रेटिंग उन्नयन 18 साल के अंतराल के बाद आया है।

एसएंडपी ग्लोबल के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2024 के बीच वास्तविक जीडीपी वृद्धि औसतन 8.8% रही, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक है। एसएंडपी ने वित्त वर्ष 2026 में 6.5 प्रतिशत और अगले तीन वर्षों में 6.8% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है।

हाल ही में, **फिच रेटिंग्स** ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग (आईडीआर) को स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'बीबीबी-' पर बरकरार रखा है, जिसका कारण भारत द्वारा वृहद स्थिरता के साथ विकास प्रदान करने का मजबूत रिकॉर्ड और राजकोषीय विश्वसनीयता में सुधार है।



भारत की स्थिर विकास गति लचीली घरेलू मांग से प्रेरित है। ग्रामीण उपभोग मजबूत हो रहा है, शहरी खर्च बढ़ रहा है, और निजी निवेश में तेज़ी आ रही है। कई व्यवसाय लगभग पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और आगे भी विस्तार कर

रहे हैं। इस बीच, सार्वजनिक निवेश - विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे में - उच्च बना हुआ है, और स्थिर उधारी स्थितियाँ कंपनियों और परिवारों दोनों को भविष्योन्मुखी निर्णय लेने में मदद कर रही हैं।

भारत के आर्थिक उत्थान को आकार देने वाली योजनाएँ और पहल

पिछले दशक में, प्रमुख योजनाओं ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दिया है, लचीलापन मजबूत किया है, उत्पादकता बढ़ाई है और नागरिकों को सशक्त बनाया है।

उत्पादन -**आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना** घरेलू विनिर्माण के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर वस्त्र तक 14 क्षेत्रों को कवर करते हुए और ₹1.97 लाख करोड़ के परिव्यय से समर्थित, इसने ₹1.76 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया है, निर्यात को बढ़ावा दिया है और रोज़गार के अवसर पैदा किए हैं - जिससे भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक मजबूत खिलाड़ी बन गया है।

डिजिटल **इंडिया कार्यक्रम** ने कनेक्टिविटी और डिजिटल समावेशन को गति दी है, जिससे इंटरनेट की पहुंच 2014 के 25 करोड़ से बढ़कर 2024 में लगभग 97 करोड़ हो गई है। 5G रोलआउट और भारत 6G विजन के साथ, भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्था है, जो प्रौद्योगिकी-आधारित परिवर्तन के माध्यम से विकास को गति दे रही है।

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत** 56 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए हैं, जिनमें से 55% महिलाओं के खाते में हैं। यह बैंकिंग, ऋण, बीमा और पेंशन तक पहुंच प्रदान करता है, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और समावेशी विकास की रीढ़ है।

मेक **इंडिया पहल** ने रेलवे, रक्षा, खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताओं के साथ भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है, जिसके 300 से ज़्यादा कारखाने हैं, जबकि 2014 में केवल दो ही कारखाने थे।

रोजगार सृजन विकास का मूल है और **प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना का** लक्ष्य 2025 और 2027 के बीच नए रोजगार को प्रोत्साहित करके 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार, **कौशल भारत मिशन** ने पीएमकेवीवाई, जेएसएस और प्रशिक्षण योजनाओं के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्रशिक्षित किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि भारत का कार्यबल भविष्य के लिए तैयार है।

विदेश व्यापार नीति 2023-28 के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिला है, जो निर्यात, व्यापार सुगमता और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देती है, साथ ही **निर्यात संवर्धन मिशन** और **विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के माध्यम से** निवेश और रोजगार सृजन हुआ है। इसके समर्थन में, **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)** ने सार्वजनिक खरीद को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया है, जिसके तहत ₹15 लाख करोड़ से अधिक के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति और **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति** ने बुनियादी ढाँचे पर आधारित विकास को गति दी है, जिससे भारत की लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में सुधार हुआ है और निर्बाध कनेक्टिविटी संभव हुई है। इसके साथ ही, **जीएसटी** और कॉर्पोरेट करों को युक्तिसंगत बनाने जैसे कर सुधारों ने अनुपालन को सरल बनाया है और लागत कम की है, जिससे व्यापार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना है।

विनिर्माण, डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन, रोज़गार, व्यापार और बुनियादी ढाँचे से जुड़ी ये पहल मिलकर भारत को एक अधिक लचीली, आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में अग्रसर कर रही हैं। ये पहल **2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के राष्ट्र के स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।**

निष्कर्ष

“आज देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।”

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

युवा जनसांख्यिकी और निरंतर संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित होकर, भारत वैश्विक व्यापार, निवेश और नवाचार में अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। पिछले एक दशक में, यह एक आश्रित अर्थव्यवस्था से एक आत्मनिर्भर, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी महाशक्ति में परिवर्तित हो गया है। इस परिवर्तन के मूल में आत्मनिर्भर भारत है, जो नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी संप्रभुता को बढ़ावा दे रहा है। पीएलआई योजनाएँ, एमएसएमई पुनरोद्धार और डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार जैसी पहल एक उच्च-विकास, उच्च-अवसर वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रही हैं।

जून के अंत तक की तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षा से कहीं अधिक तेज़ 7.8% की वार्षिक दर से बढ़ी, जिसे विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्रों ने बढ़ावा दिया। और वित्त वर्ष 26 के लिए भारत का विकास परिदृश्य आशाजनक है। निजी निवेश में तेज़ी, बढ़ता उपभोक्ता विश्वास, वेतन वृद्धि और मज़बूत कृषि उत्पादन द्वारा समर्थित लचीली ग्रामीण माँग इसके प्रमुख प्रेरक हैं। कम होती खाद्य मुद्रास्फीति और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ, ये कारक भारत की मध्यम अवधि की विकास क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करते हैं।

संदर्भ

पीआईबी पृष्ठभूमि/प्रेस विज्ञप्ति

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=154660&ModuleId=3>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=155053&ModuleId=3>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=154962&ModuleId=3>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=154980&ModuleId=3>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=154686&ModuleId=3>

<https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149260>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2147906>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2161834>

<https://www.pib.gov.in/pressreleasepage.aspx?PRID=2161516>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2156749>

भारत का बजट

<https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap01.pdf>

आर्थिक मामलों का विभाग

https://dea.gov.in/sites/default/files/Monthly%20Economic%20Review%20June%202025_0.pdf

एसबीआई.co.in

https://sbi.co.in/documents/13958/43951007/8%2Byears%2Bof%2BGST_SBI%2BResearch.pdf/266da3f2-1271-e0f2-ac66-22184bf9391e?t=1753163204146

डीडी न्यूज़

<https://ddnews.gov.in/en/rbi-retains-indias-gdp-growth-forecast-at-6-5-for-fy-2025-26/>

न्यूज़ऑनएयर.gov.in

<https://www.newsonair.gov.in/over-11-lakh-aspirants-got-jobs-in-last-16-months-under-rozgar-mela-mansukh-mandaviya/>

आईबीईएफ

<https://www.ibef.org/economy/indian-economy-overview>

<https://www.ibef.org/economy/foreign-direct-investment>

[https://www.ibef.org/blogs/special-economic-zones-in-india-catalysts-for-economic-growth-and-global-](https://www.ibef.org/blogs/special-economic-zones-in-india-catalysts-for-economic-growth-and-global-competitiveness#:~:text=Special%20economic%20zones%20(SEZ)%20are,export%20processing%20zones%20(EPZs).)

[competitiveness#:~:text=Special%20economic%20zones%20\(SEZ\)%20are,export%20processing%20zones%20\(EPZs\).](https://www.ibef.org/blogs/special-economic-zones-in-india-catalysts-for-economic-growth-and-global-competitiveness#:~:text=Special%20economic%20zones%20(SEZ)%20are,export%20processing%20zones%20(EPZs).)

PMindia.gov.in

[https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/highlights-from-the-pms-address-on-the-79th-independence-](https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/highlights-from-the-pms-address-on-the-79th-independence-day/#:~:text=This%20grand%20festival%20of%20Independence,crore%20resolutions%20of%20our%20people.&text=India%20is%20continuously%20strengthening%20the%20spirit%20of%20unity.&text=For%2075%20years%2C%20the%20Constitution,guiding%20us%20like%20a%20lighthouse.)

[day/#:~:text=This%20grand%20festival%20of%20Independence,crore%20resolutions%20of%20our%20people.&text=India%20is%20continuously%20strengthening%20the%20spirit%20of%20unity.&text=For%2075%20years%2C%20the%20Constitution,guiding%20us%20like%20a%20lighthouse.](https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/highlights-from-the-pms-address-on-the-79th-independence-day/#:~:text=This%20grand%20festival%20of%20Independence,crore%20resolutions%20of%20our%20people.&text=India%20is%20continuously%20strengthening%20the%20spirit%20of%20unity.&text=For%2075%20years%2C%20the%20Constitution,guiding%20us%20like%20a%20lighthouse.)

एनसीपीआई.ORG.IN

<https://www.ncpi.org.in/what-we-do/upi/product-statistics>

pmjdy.gov.in

<https://www.pmjdy.gov.in/scheme>

gem.gov.in

<https://gem.gov.in/>

फिच रेटिंग्स

<https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-india-at-bbb-outlook-stable-25-08-2025#:~:text=Fitch%20Ratings%20%2D%20Hong%20Kong%20%2D%2025,%20with%20a%20Stable%20Outlook.>

पीके/केसी/एनकेएस/डीए